फैक्टरियों में विस्तार के लिये आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा करने के लिये 10 सदस्यों की एक नई समिति गठित की है।

(ख) मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा लाइसेंस देने के लिये क्षमता की चरणबद्ध उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये सामयिक लंबित आवेदन पत्रों की संवीक्षा करने के लिये समय समय पर अपनी बैठक बुलायेगी।

(ग) महाराष्ट्र राज्य में 30-9-91 तक नई चीनी फैक्टरियों की स्थापना के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु लंबित प्रस्तावों की सूची उपाबंध पर है। जांच समिति/लाइसेंसिंग समिति द्वारा इन आवेदन पत्रों की संशोधित लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार संवीक्षा की जायेगी।

[देखिये परिशिष्ट 161, अनुबंध संख्या 16]

(घ) जैसा कि ऊपर (ख) में उत्तर दिया गया है।

प्राथमिक विद्यालय

840. मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिये क्या मापदंड हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश के उन स्थानों के नाम क्या हैं जो इन मापदंडों को पूरा करते हैं परन्तु वहां पर कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है; और

(ग) वहां पर कब तक ऐसे विद्यालयों के खोले जाने और उनके लिये भवन निर्माण कराये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) देश भर में प्राईमरी स्कूलों को खोलने के लिये कोई सख्त मानदंड नहीं बनाये गये हैं। केन्द्र सरकार ने, राज्य सरकारों से सिफारिश की है कि 300 की जनसंख्या (मरूस्थलीय, जनजातीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में 200) वाली सभी बस्तियों में एक-एक प्राईमरी स्कूल खोलने की व्यवस्था की जानी चाहिये और सभी बच्चों को उनके निवास स्थान से एक कि०मी० की दूरी के अन्दर ही प्राईमरी शिक्षा की सुविधा व्यवस्था करने के लिये प्रयास किये जाने चाहिये। प्रत्येक राज्य अपनी जरूरतों एवं नीति के अनुसार मानदंड निर्धारित करता है और प्राईमरी स्कूलों को खोलने और भवनों के निर्माण के संबंध में भी स्वयं ही निर्णय लेता है। वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा संचालित पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक की जनसंख्या वाली लगभग 14,300 बस्तियों में प्राईमरी स्कूल नहीं हैं।

Literacy rate in Arunachal Pradesh

841. SHRI NYODEK YONGGAMl: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the present rate of literacy in Arunachal Pradesh, districtwise; and

(b) what steps Government have taken so far to increase the percentage of literacy in that States indicating the expenditure incurred for the purpose during the last two years?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) According to 1991 census, the provisional literacy rate in the state of Arunachal Pradesh for the population aged 7 years and above is 41.22%. The literacy rate for the districts of Arunachal Pradesh cannot be calculated till the popualtion in the age-group 0-6 is tabulated. However, the position regard-